जल्द मिलेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, पीएम करेंगे शिलान्यास

एसोचैम के एमएसएमई सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई के बीच एक हजार एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाला पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क जल्द मूर्त रूप लेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक-दो माह में इस मेगा परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के एमएसएमई सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के साथ बुनकरों व कारीगरों के लिए यह बड़ा उपहार होगा।

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान होटल हयात रीजेंसी में सोमवार को आयोजित उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते • जागरण

- **ओडीओपी उत्पादों के लिए वाराणसी, आगरा व लखनऊ में बनेंगे यूनिटी माल**

मंत्री राकेश सचान ने एक जिला एक उत्पाद योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी योजना शुरू की और प्रधानमंत्री ने इसे पूरे विश्व में फैलाया। ओडीओपी कारीगरों, हस्तशिल्पयों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए वाराणसी, लखनऊ और आगरा में यूनिटी माल बनाए जाएंगे। छोटे उद्यमों के समक्ष पैकेजिंग की बड़ी समस्या है। इसलिए राज्य सरकार का प्रयास है कि लखनऊ में पैकेजिंग का भी एक संस्थान खोला जाए। प्रदेश में 90 लाख छोटे उद्योगों में से महज 14 लाख का ही पंजीकरण है। राज्य सरकार इनको पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन दे रही है। एमएसएमई को पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। मंत्री ने निर्यात के आंकड़ों को भी साझा किया। कहा, वर्ष 2019-20 में 86 हजार करोड़ रुपये का निर्यात प्रदेश से होता था, 2022-23 में यह बढ़कर 1.74 लाख करोड़ हो गया है। छोटे उद्यमियों को बैंकों से कर्ज मिलने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपये तक का लोन लेने वालों को सुविधा देते हुए उनकी गारंटी देने का निर्णय लिया है। इससे कर्ज मिलने में आसानी होगी।

छोटे उद्यमों को 25 लाख करोड़ के अतिरिक्त वित्त समर्थन की जरूरत : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिवसुब्रमणियम रमण ने कहा कि गैर पंजीकृत एमएसएमई की वित्तीय जरूरत को पूरा करना चुनौती है। देश में करीब 1.6 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई हैं, जबकि सात करोड़ के आसपास बिना पंजीकरण वाले एमएसएमई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने नियमों के चलते इन्हें कर्ज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इन उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए सिडबी इस पर विचार कर रहा है। छोटे उद्यमों में अगले तीन चार साल के दौरान अतिरिक्त 25 लाख करोड़ रुपये तक के वित्त समर्थन की जरूरत होगी। एसोचैम की डब्ल्यूटीओ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की नेशनल काउंसिल अध्यक्ष सुहैल नैथाणी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से एमएसएमई को नई ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। एसोचैम के बिजनेस फेसिलिटेशन के सह-अध्यक्ष रामचंद्रन वेंकटरमन, एनपीसीआइ के अभिषेक कुमार स्वर्णकार और एसोचैम यूपी के सह-अध्यक्ष अनुपम मित्तल ने भी अपने विचार रखे।